आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 13.12.2023 से 17.12.2023)

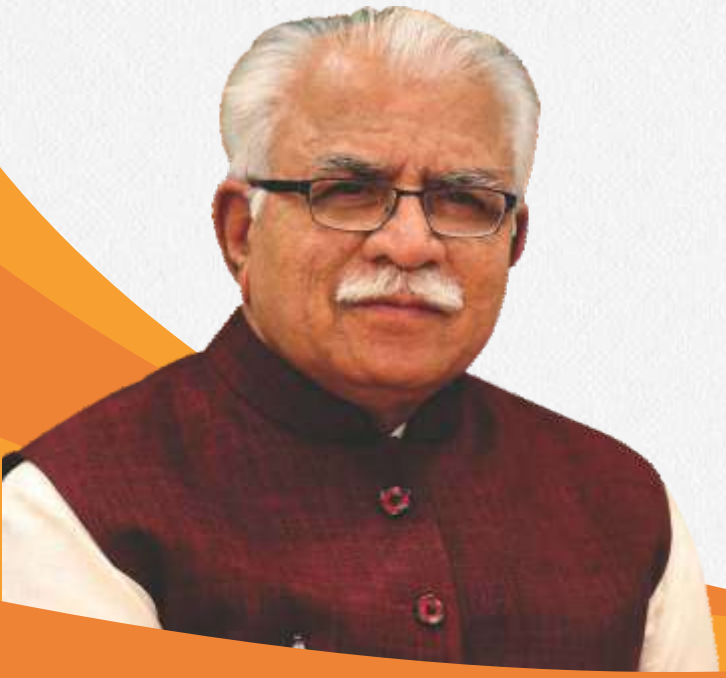

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

भ्रष्टाचार पर एक्शन

(दिनांक 13.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में **जनता को पारदर्शी शासन प्रदान करने के दृष्टिगत भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है।** इसी कड़ी में सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर सख्त कार्यवाही करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन नंबर–2, सोनीपत के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा को निलंबित कर दिया है और साथ ही उसके विरुद्ध नियम–7 के तहत विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय से सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की

साप्ताहिक सूचना पत्र

निगरानी कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल जी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोनीपत के निवासी दीपक, जोकि एक ठेकेदार है, ने **सीएम विंडो पर कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध कोटेशन को सेंक्शन करने के लिए उनसे 20 प्रतिशत एडवांस कमीशन की मांग करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।**

ओएसडी ने बताया कि उपरोक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच हेतु विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई और कमेटी की जांच रिपोर्ट में कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाये गए। तदानुसार **माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितेंद्र सिंह हुड्डा को निलंबित करने के साथ–साथ नियम–7 के तहत विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।** श्री भूपेश्वर दयाल जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश

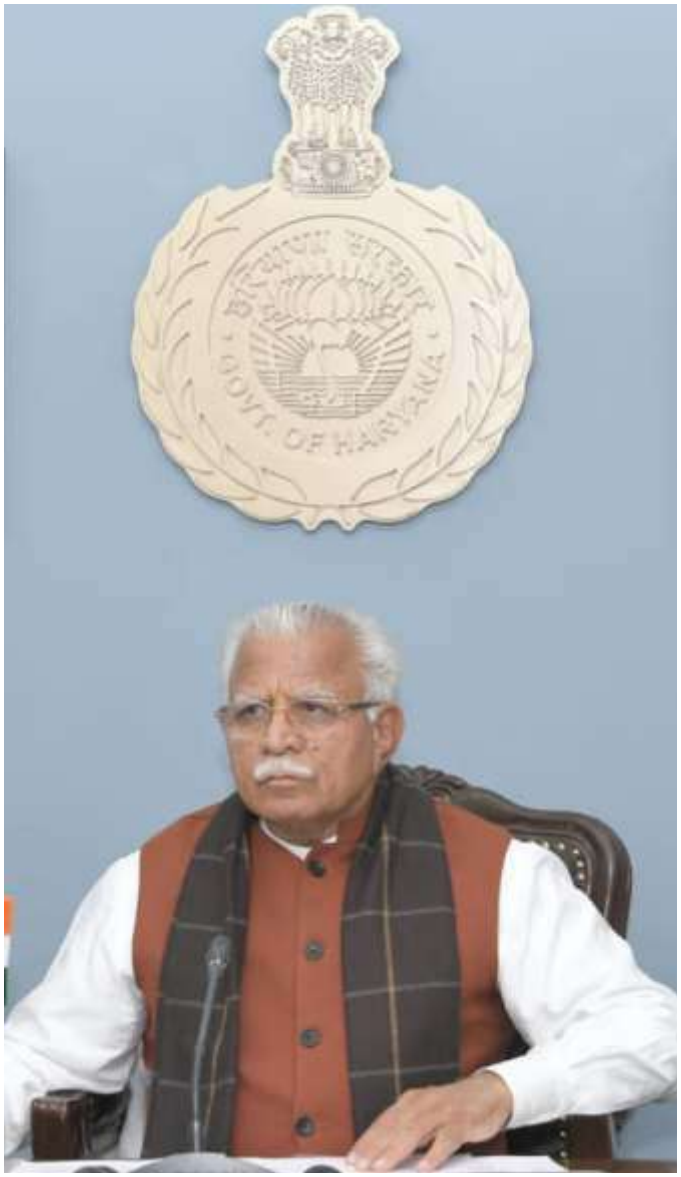

दिया गया है कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, तो भविष्य में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुपर 100 कार्यक्रम के सभी छात्र–छात्राओं को शुभकामनाएं

(दिनांक 13.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू किया गया **सुपर–100 कार्यक्रम के सभी छात्र–छात्राओं को बधाई दी जो इस सफलता का हिस्सा बने** हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित किया है कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है तो वे भी किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। **हरियाणा सुपर 100 कार्यक्रम ने इसी उदाहरण को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है और हम उन सभी छात्रों को प्रेरित करते हैं जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं।** इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से

साप्ताहिक सूचना पत्र

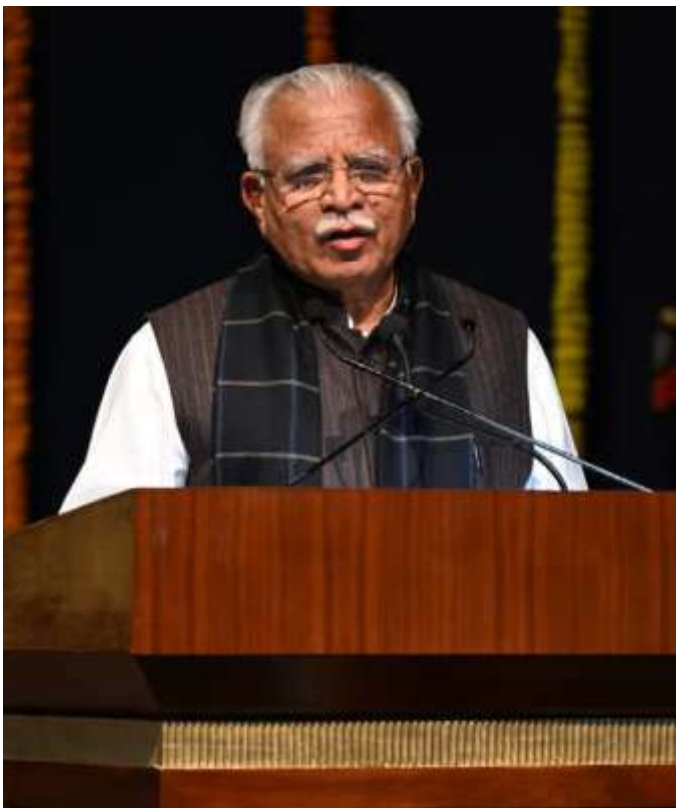

लगाया जा सकता है कि सुपर 100 कार्यक्रम की पहली छात्रा काजल को माइक्रोसॉफ्ट से 31 लाख की सैलरी का पैकेज ऑफर हुआ है। **वहीं सुपर 100 कार्यक्रम के पहले बैच के एक अन्य छात्र प्रवीण को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर ट्रेसाटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से 18 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है।** उल्लेखनीय है कि सुपर 100 प्रोग्राम के पहले बैच के छात्र इस साल कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हो रहे हैं। भविष्य में और भी कई छात्रों का चयन होने की उम्मीद है। दोनों छात्रों ने साझा किया कि सुपर 100 कार्यक्रम ने उनकी इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान किया है। इस कार्यक्रम ने उन्हें सही मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्होंने अपनी क्षमताओं को पूरे पोटेंशियल तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।

उल्लेखनीय है कि **सुपर–100 कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर अब तक सैकड़ों विद्यार्थी आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुँच चुके** हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम बहुत ही सफल एवं कारगर है जिसके माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थियों ने वांछित सफलता पाई है जो सरकार की शिक्षा नीति का परिणाम है। **सरकार ने अब सुपर–100 कार्यक्रम को बढ़ाकर सुपर–600 कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके।**

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों को किया गया समायोजित

(दिनांक 13.12.2023)

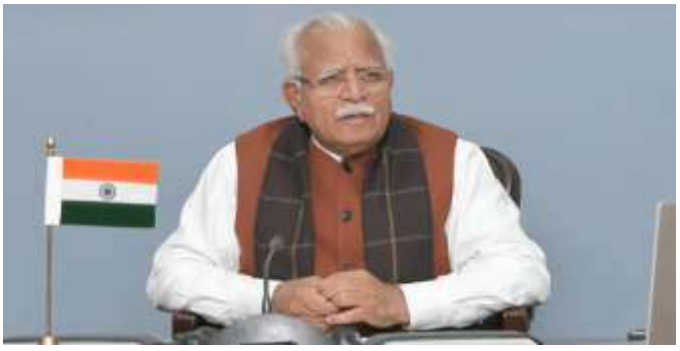

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कच्चे कर्मचारियों को **ठेकेदारों के चंगुल से बचाने के लिए आउटसोर्सिंग पालिसी को तर्कसंगत बनाकर लगभग 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करके मनोहर तोहफा दिया** है। इसके अलावा कर्मचारियों के नाम पर राजनीति करने वाले सो कॉल्ड कर्मचारी यूनियनों के प्रधानों को करारा जवाब दिया है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। **कच्चे कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान व ईएसआई के नाम पर ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण की शिकायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया** है और कर्मचारियों को एक ही छत्त के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया है।

गत 9 वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से **मेरिट आधार पर पूरा कर 1 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी** हैं। इसके अलावा लगभग 60 हजार से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

जिन विभागों में तत्काल कार्य बल की आवश्यकता है ,उसे पूरा करने के लिए **हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अहम भूमिका निभा रहा है। लगभग 20 दिनों में विभागों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को नौकरी के जॉब ऑफर लेटर जारी** किए जाते हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रेस वार्ता को संबोधित करना

(दिनांक 14.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी **2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 तय की** है।

इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सडक़ें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। **अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए**

ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित होती हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है, ताकि लोग सस्ते मकान ले सकें। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोग नियमित कॉलोनियों में ही अपने मकान बनाएं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाई माह में हुई भारी बारिश व बाढ़ के कारण लगभग 12 जिलों में हुए फसली, संपत्ति, पशुधन व वाणिज्यिक संपत्तियों सहित हुए भारी नुकसान के लिए **34,511 किसानों को मुआवजा स्वरूप 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपये की राशि दी।**

एक पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को दिए गए मुआवजा राशि में 49 हजार 197 एकड़ का वह क्षेत्र भी शामिल है, जिसकी पुनः बिजाई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा पहले ही की गई थी। उन्होंने कहा कि आज दिए गए मुआवजे में कपास की फसल शामिल नहीं है। इसका सर्वे अभी चल रह है। उन्होंने कहा कि **शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक सम्पत्तियों के नुकसान के लिए 6 करोड़ 70 लाख 97 हजार 277 रुपये की मुआवजा राशि अनुमोदित की गई** है।

इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि **ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन, घरों, वाणिज्यिक संपत्तियों की क्षति, कपड़ों, बर्तनों व अन्य घरेलू सामान की क्षति के लिए 5 करोड़ 96 लाख 83 हजार रुपये की राशि 11 अक्तूबर 2023 को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे ही बैंक खातों में डाली गई है।** उन्होंने कहा कि बाढ़ में 47 लोगों की मृत्यु हुई थी। सरकार ने उनके परिजनों को 4–4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। इनमें से 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपये

की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा **विधुर तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक अनूठी पहल कर समाज के समक्ष सेवा एवं सम्मान का नया उदाहरण प्रस्तुत किया** है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 12,882 विधुर तथा 2,026 अविवाहितों की पहचान कर ली गई है। इन्हें 1 दिसम्बर, 2023 से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी **सरकार ने विधुर एवं अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया** है और इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष आयु के विधुर तथा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित (पुरुष और महिला) पात्र हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि **जल्द ही हरियाणा को उसका अपना राज्य गीत मिलेगा।** 15 दिसंबर, 2023 से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि **विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सरकार ने 3 गीतों का चयन किया है और सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा। मतों के आधार पर सर्वाधिक वोट मिलने वाले गीत को एक साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा।** उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देशभर में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला है।

प्रेस वार्ता के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने **हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थाई नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे।** उन्होंने कहा कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया है और नये सिरे से भी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम के तहत लोगों को नौकरी देने के कुछ मानदंड तय किए गए हैं,

साप्ताहिक सूचना पत्र

जिसके तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर कहा कि प्रदेश के लोगों को टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में **महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की है। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं।** एसवाईएल पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के क्रियान्वयन करने में गम्भीर है। पानी की उपलब्धता व आवश्यकता अलग विषय है और नहर का बनना अलग है। पानी के हिस्से के बारे में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के लिए ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 28 दिसम्बर, 2023 को चण्डीगढ़ में दोनों राज्यों (पंजाब–हरियाणा) के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्रुप–डी कर्मचारियों के लिए संशोधित स्थानांतरण नीति घोषित

(दिनांक 14.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी ने कहा कि राज्य सरकार ने **हरियाणा ग्रुप–डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 (कॉमन कैडर) के तहत आने वाले ग्रुप–डी कर्मचारियों के लिए अपनी स्थानांतरण नीति में सुधार किया** है।

मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे पत्र में कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।

अधिनियम के लागू होने के बाद से ग्रुप–डी पदों पर नियुक्त कुछ कर्मचारियों ने स्वयं को अपने गृह–नगर से दूर या कार्य की प्रकृति के कारण अनुपयुक्त नौकरियों पर तैनात पाया है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए **राज्य सरकार सामान्य कैडर के भीतर पात्र कर्मचारियों को पुनः आवंटित करने**

के लिए एक स्थानांतरण अभियान शुरू कर रही है। कर्मचारी निर्दिष्ट पोर्टल पर अवांछित पदों को इंगित करें और पसंदीदा जिलों को प्राथमिकता दें। इस अभियान के लिए एचआरएमएस में कुल रिक्त पदों में से केवल 80 प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत अनुपलब्ध होगा और विभाग–वार और पद–वार गणना की जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विधानसभा का शीतकालीन सत्र

(दिनांक 15.12.2023)

प्रभाव : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सदन में अदम्य साहस व वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 18 वीर सैनिकों के निधन

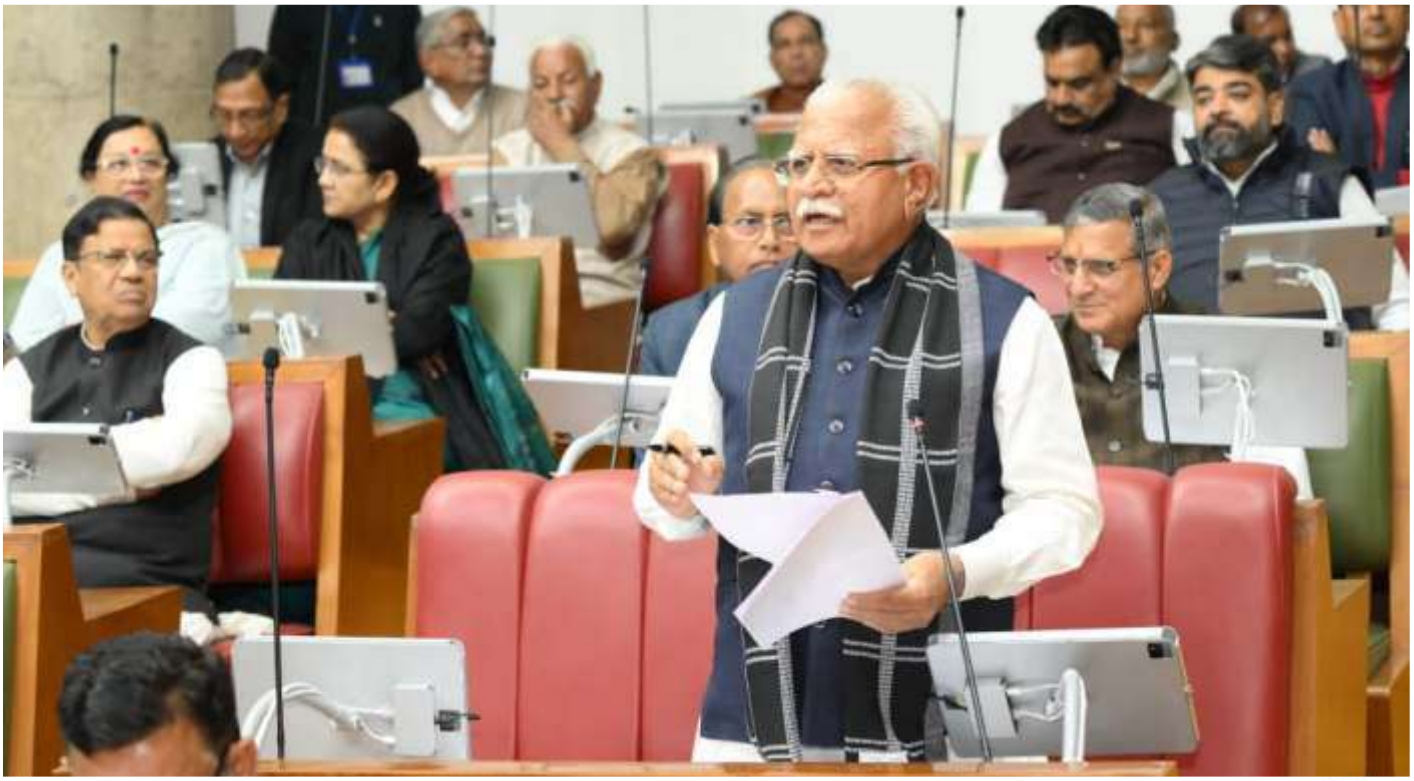

साप्ताहिक सूचना पत्र

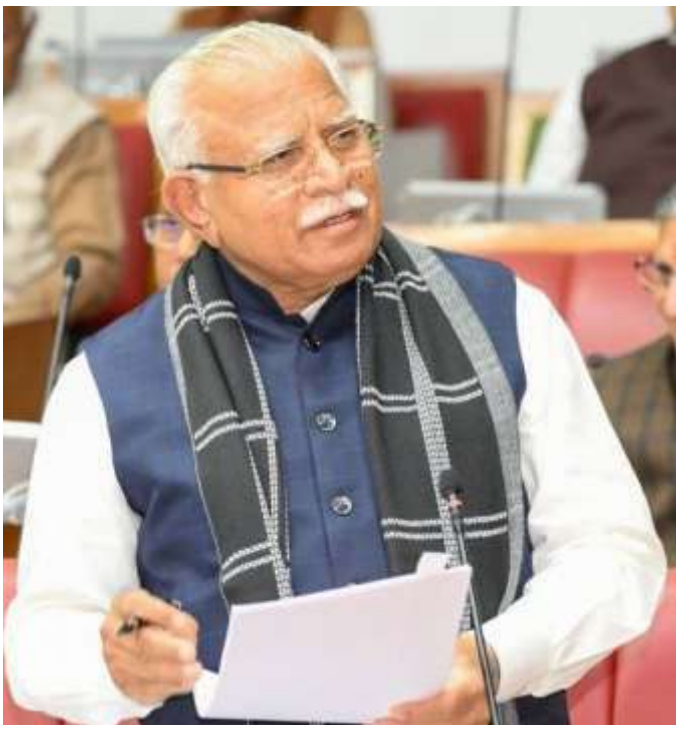

पर भी शोक व्यक्त किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन **सत्र के पहले दिन हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला राज्य गीत सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया।** सरकार द्वारा चयनित 3 गीतों को सदन में सुनाया गया, जिन पर सदस्यों द्वारा एक गीत को चुनकर उसे एक साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व–वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य–चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य–गीत नहीं है, जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों।

एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। मुझे आशा है कि राज्य गीत राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक श्री वरुण चौधरी

द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 1976 से पहले गजेटेड और नॉन गैजेटेड के वेतन, अलाउंस इत्यादि के बिल निकालने का अलग नियम था। इसके अनुरूप राजपत्रित अधिकारी स्वयं के बिल और सैलरी बिल स्वयं साईन करके तथा गैर राजपत्रित अधिकारी डीडीओ के माध्यम से बिल निकलवा सकते थे।

लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने 12 जुलाई, 1976 को यह व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथोराइज कर दिया।माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह विषय 47 साल पुराना है, लेकिन किसी ने यह विषय कभी नहीं उठाया, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की 21. 5 साल, आईएनएलडी की 11.5 साल, हरियाणा विकास पार्टी की 3.5 सालों तक सरकारें रही। 1976 में नियमों में जो भी बदलाव किया गया, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था और वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का

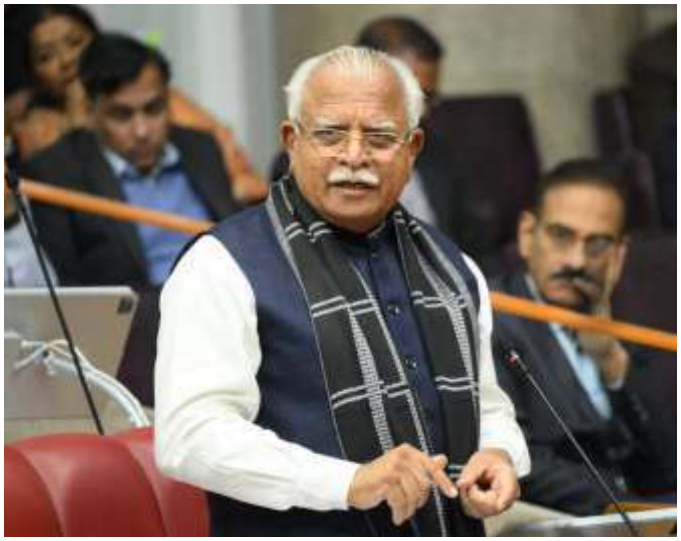

बदलाव का कोई विचार नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदस्य जनहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने **प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री चिरंजीव राव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा।** हरियाणा सरकार निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है और टेंडर प्रक्रिया इत्यादि जल्द ही शुरू हो जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल सुधार के लिए सरकार के सकारात्मक कदम

(दिनांक 15.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का मौलिक आधार है और **सरकार प्रतिबद्ध है कि हर एक बच्चे को उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे उन्नत, समर्पित और समर्थ नागरिक बन सकें।** सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसका **एक पहलू शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार** है ताकि हर एक स्कूल में उच्चतम स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं हों। वहीं इसका **दूसरा पहलू पढ़ाई में नए पाठ्यक्रम और तकनीकी साधनों का प्रयोग** है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा टैबलेटों का वितरण कर बच्चों को तकनीकी गतिविधियों के साथ जोड़कर उन्हें एक नई शैली में शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु सरकार ने 49 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14 हजार से अधिक सरकारी स्कूल हैं जिनमें से केवल 1952 स्कूलों में ही बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई। इन कमियों को भी अब दूर किया जा चुका है।इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक 1738 करोड़ रुपये में से 580 करोड़ रुपये दिए गए। **इस उपलब्ध बजट में से, विभाग ने अब तक लगभग 302 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की** है, जिसमें से लगभग 167 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही संबंधित ठेकेदार/निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जीने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नए प्रयासों का संकल्प लिया है और इसके माध्यम से विभिन्न पहलुओं में शिक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

वर्ल्ड कबड्डी संस्था के प्रतिनिधिमंडल से भेंट

(दिनांक 16.12.2023)

प्रभाव : हरियाणा के **पारंपरिक खेल कबड्डी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे है।** इसके लिए आज **'वर्ल्ड कबड्डी'** नामक संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने हिपसा अध्यक्ष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से औपचारिक भेंट कर हरियाणा को कबड्डी विशेषकर महिला कबड्डी को बढ़ावा देने में लीड करने का आग्रह किया है। इस प्रतिनिधि मंडल में वर्ल्ड कबड्डी संस्था के अध्यक्ष श्री अशोक दास (इंग्लैंड), महासचिव एसटी अरासू (मलेशिया) व श्रीमति कवल राज (इंग्लैंड), उपाध्यक्ष डा. ओसामा सैद हाशम (मिश्र), कार्यकारिणी सदस्य सुश्री परपेचुअल म्बूतु (केनिया) शामिल थे।

सरकार पहले से ही बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने हरियाणा के पारंपरिक खेल कबड्डी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास की प्रशंसा की।

माननीय **मुख्यमंत्री जीने हिपसा व वर्ल्ड कबड्डी के प्रतिनिधियों से कहा कि आप कबड्डी का देश विदेश में प्रसार करें** और **इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग देने को तैयार है।** माननीय मुख्यमंत्री जीने अपनी खेल के प्रति भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि कबड्डी उनका भी पसंदीदा खेल रहा है और अब भी जब कहीं राहगिरी का कार्यक्रम होता है तो उसमें कभी कभी कबड्डी खेल में वे हिस्सा लेकर दूसरों

को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जब महिला कबड्डी के विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की इस मुहिम का पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे क्योंकि वे भी स्थानीय खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं।

इस प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जीको बताया कि **उनका संगठन विश्व के 50 से अधिक देशों में सक्रियता से काम कर रहा है। हिपसा के साथ मिलकर इस संगठन का लक्ष्य विश्व स्तर पर कबड्डी खेल (नेशनल स्टाइल) को बढ़ावा देना है** और इस खेल को ओलंपिक में शामिल करवाना है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि उनका लक्ष्य महिला कबड्डी (नेशनल स्टाइल) का पहली बार वर्ल्ड कप करवाना है। इसके लिए पहले चरण में 20 देशों की पहचान की गई है और हर वर्ष 20 नए देश जोड़े जाएंगे। इस प्रकार पूरे विश्व में महिला कबड्डी का प्रसार होगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि **सन 2019 से वे हर वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड**

कबड्डी डे मनाते आ रहे हैं और वर्ष 2024 में इस दिवस का थीम– '**कबड्डी क्रिएटिड बाय मेन एंड परफेक्टिड बाई विमेन**' रखा गया है। पूरे साल इस थीम के साथ महिला कबड्डी को लोकप्रिय बनाने के प्रयास होंगे। इस प्रकार हरियाणा के पारंपरिक खेल कबड्डी को दुनिया में पहचान दिलाने का यह पहला विश्व स्तरीय प्रयास होगा। हिपसा की अध्यक्ष श्रीमति कांथि डी. सुरेश ने कहा कि उनकी संस्था कबड्डी खेल को विश्व भर में प्रसारित करवाने में पूरा सहयोग देगी और हरियाणा इस मुहिम से जुड़ेगा तो कबड्डी को जल्द लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम किसानों से संवाद

(दिनांक 16.12.2023)

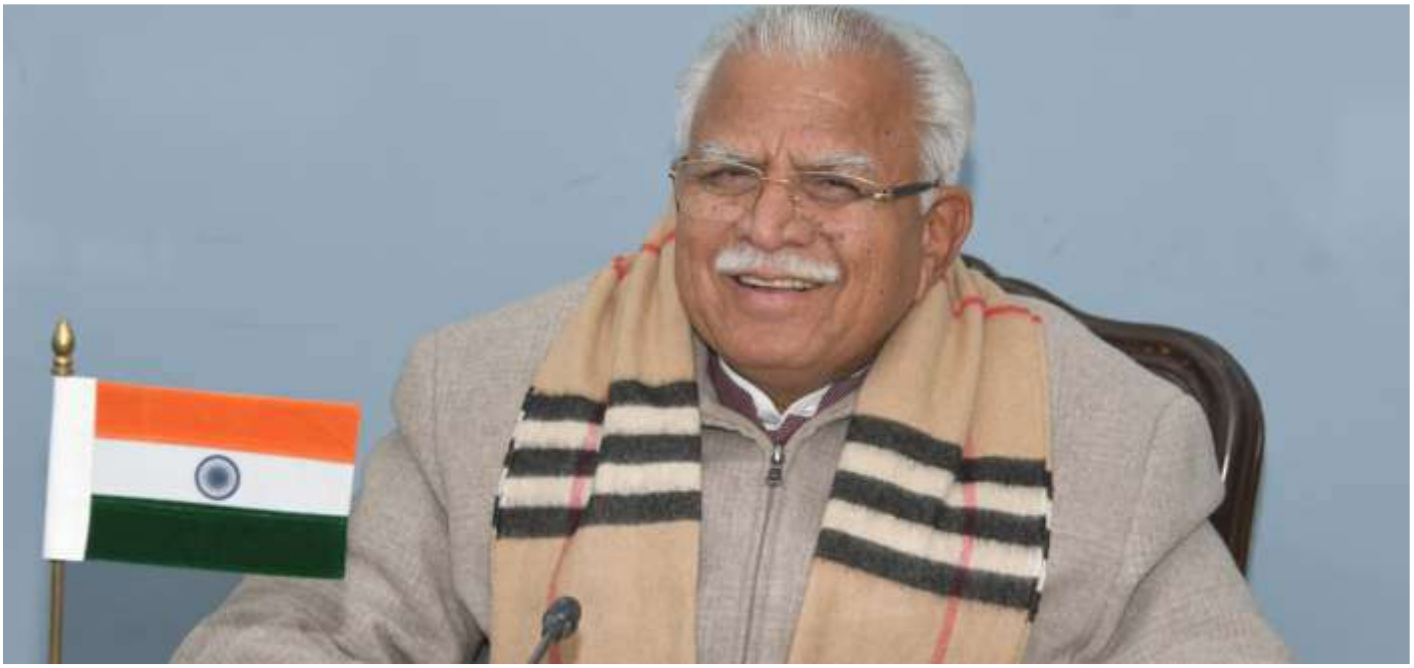

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के किसान कड़ी मेहनत करके देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार किसानों की हितैषी है। पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी है, जिसमें पिछली सरकार की बकाया 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि भी शामिल है। **सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के सत्यापन और प्रभावित लोगों को मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था, जोकि कारगर साबित हुआ है।**

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी नेकहा कि उन ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाता है, जो फसल अवशेष जलाने के मामले में अति संवेदनशील गांवों की श्रेणी से निकलकर शून्य फसल अवशेष जलाने की श्रेणी में आ जाती हैं। इसी प्रकार से उन पंचायतों को 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाता है, जो संवेदनशील गांवों की श्रेणी से निकलकर शून्य फसल अवशेष जलाने की श्रेणी में आ जाती हैं। उन्होंने बताया कि **धान की खेती में पानी की अधिक खपत को देखते हुए इसके स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना चलाई है।** इसके तहत धान क्षेत्र के अन्य फसलों से विविधिकरण हेतु 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

प्रदेश के किसानों को अब तक 685 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष में **अब**

तक 6,130 मशीनें किसानों द्वारा अनुदान पर खरीदी गई हैं। इन मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इन–सीटू एवं एक्स सीटू प्रबंधन करने पर 1,000 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक लगभग 1 लाख 42 हजार किसानों ने 13.1 लाख एकड़ धान क्षेत्र को प्रबंधित करने हेतु पंजीकरण करवाया है, जिस पर किसानों को लगभग 131 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 2 लाख 50 हजार एकड़ भूमि में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिकम्पोजर किट किसानों को नि–शुल्क उपलब्ध करवाई गई है।

पराली का उपयोग कर बिजली बनाने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जींद में बायोमास परियोजनाएं शुरू की गई, जिनसे 30 मेगावाट विद्युत उत्पन्न हो रही है।

इसके अलावा, **पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में भी किया जा रहा है।** पानीपत रिफाइनरी में 2जी के बाद अभी 3जी प्लांट भी में लग गया है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3जी इथेनॉल प्लांट होगा। 2जी इथेनॉल प्लांट में पराली की खपत सुनिश्चित करने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि **'पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना' की 15वीं किस्त के लाभार्थी किसान भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं।** प्रदेश के 8 लाख 74 हजार किसानों को किस्त के तौर पर 175 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेती की जमीन कम हो रही है। सरकार की अफ्रीकी देशों से बात हुई है। हमारे किसान वहां जाकर खेती कर सकेंगे। इसके लिए सरकार योजना बना रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी नेकहा कि हमारे किसानों ने पराली प्रबंधन की अच्छी मिसाल पेश की है। पराली प्रबंधन में हरियाणा आदर्श राज्य बना है। प्रदेश में पराली जलाने की कम घटनाएं हुई हैं। इसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि **सरकार किसानों के कल्याण व उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दिशा में खेत में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक हर कदम पर सरकार ने किसानों की मदद की है।** उन्होंने बताया कि इसी साल जुलाई महीने में बाढ़ के कारण 12 जिलों में 1469 गांव और 4 शहर प्रभावित हुए थे। **सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को पूरा सहयोग किया है। 112 करोड़ 21 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी है।** फसल खराब के लिए 34 हजार 511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

एम्स को रेवाड़ी–नारनौल रोड (एनएच–11) से जोड़ने के लिए आरओबी के निर्माण को मंजूरी

(दिनांक 16.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां एम्स को **रेवाड़ी – नारनौल रोड (एनएच–11) से जोड़ने के लिए आरओबी के निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी दी।**

रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाइन और रेवाड़ी नारनौल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लाइन पर 251.08 करोड़ रुपये की लागत से एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाने से रेवाड़ी जिले में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को अत्याधुनिक पहुंच प्रदान की जाएगी।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित आरओबी एम्स साइट को रेवाड़ी – नारनौल रोड (एनएच–11) के साथ निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रमुख घटक है। आरओबी का रुख रेवाड़ी और नारनौल दोनों तरफ से शुरू करने का प्रस्ताव है। इस **आरओबी के निर्माण से मरीजों, चिकित्सा पेशेवरों और आगंतुकों के लिए एम्स तक त्वरित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे अधिक सुलभ और रोगी–अनुकूल स्वास्थ्य देखभाल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।**

प्रवक्ता ने आगे बताया कि जिला प्रशासन ने एम्स परियोजना के लिए माजरा मुस्तकिल भालखी गांव में 15 एकड़ भूमि का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास में मजबूत बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार द्वारा एक ऐसा वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है जो सभी नागरिकों के लिए विकास और कल्याण को प्रोत्साहन देगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अहम बैठक

(दिनांक 17.12.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला नगर आयुक्तों के साथ **हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।**

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के नागरिकों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और योजनाओं का मौके पर ही लाभ देने के लिए शुरू की गई **विकसित भारत संकल्प यात्रा से दिन–प्रतिदिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है। केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेवारी है।**

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु सरकार आपके द्वार की अवधारणा पर चलते हुए जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

अब हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ा है, ताकि लोगों को केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने के साथ–साथ उनकी समस्याओं व शिकायतों का समाधान भी मौके पर ही सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान जहां–जहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें हर विभाग के अधिकारी की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी नागरिक को खाली हाथ न लौटना पड़े। उनकी शंकाओं का तुरंत समाधान किया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में स्वच्छता अभियान पर

साप्ताहिक सूचना पत्र

पूरा फोकस किया जा रहा है, इसलिए शहरों में कहीं पर भी कूड़ा–कचरे के ढेर दिखाई नहीं देने चाहिए, यह जिला प्रशासन के अधिकारी सुनिश्चित करें। **अगले सप्ताह से सीएम टीम या अधिकारी शहरों में अचानक दौरा करेगी** और इस प्रकार के कचरे के ढेर दिखाई दिए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद से अब तक 11 लाख 19 हजार से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और दिन–प्रतिदिन यह संख्या बढ़ रही है। **यात्रा के दौरान 1871 ग्राम पंचायतों और 51 शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका हैं।** इन कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही **योजनाओं की जानकारी देकर उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही, हेल्थ चेकअप पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।** केंद्र व राज्य सरकार अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार जनता तक यही इस यात्रा का ध्येय है, इसलिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव

(दिनांक 17.12.2023)

प्रभाव : माननीय उप राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती व महापूजन कर विधिवत रूप से 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव–2023 का शुभारम्भ किया।

पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती व **महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव–2023 का आगाज हुआ।**

यहां पर देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने–अपने प्रदेश की वेशभूषा में सुसज्जित होकर लोक नृत्यों पर झूमकर दूर–दराज से आए मेहमानों और पर्यटकों का कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचनें पर खुशी का इजहार किया। इसके पश्चात **माननीय उप राष्ट्रपति व माननीय मुख्यमंत्री**

जी ने ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का आचमन कर पूजा अर्चना की और पवित्र ग्रंथ गीता पर पुष्प अर्पित कर पूजन किया तथा गीता महाआरती में भाग लिया।

इस महोत्सव में 18 हजार विद्यार्थियों के साथ वैश्विक गीता पाठ, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केन्द्र पटियाला, हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता

साप्ताहिक सूचना पत्र

सेमिनार, संत सम्मेलन, ब्रहमसरोवर की महाआरती, दीपोत्सव, 48 कोस के 164 तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहेंगे।

इसके लिए प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए है। माननीय उप राष्ट्रपति जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश गौरवशाली इतिहास के साथ विकासात्मक स्वरूप का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जहां गीता की जन्मस्थली पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश दे रही है, वहीं हरियाणा सरकार की विकासात्मक उपलब्धि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा को अतुलनीय पहचान दे रही है।

माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में शिरकत की तथा गणमान्य अतिथियों के साथ संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। **माननीय उपराष्ट्रपति जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उन्हें गीता का सच्चा अनुयायी बताया।** उन्होंने

कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है तो वहीं ये पारदर्शिता, सुचिता व उत्तरदायित्वता के लिए जाने जाते हैं। **श्री मनोहर लाल जी ने गीता के संदेश को जमीनी स्तर पर सार्थक बनाया है, जब गांव के बच्चे को बिना पैसे के नौकरी का पत्र दिया है।** श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि जब–जब मुख्यमंत्री जी मुझे हरियाणा आने का निमंत्रण देते हैं, तो यहां आकर मुझे हर बार नया अनुभव व ऊर्जा मिलती है। इस बार तो कुरुक्षेत्र की धरा पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होनें कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को गीता गर्वेनेंस कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री गीता में दिए गए संदेश को अपनाते हुए कभी पथ भ्रष्ट नहीं होते और सदैव कर्तव्य करते रहते हैं। गीता में फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर्म के सिद्धांत पर चलने को कहा गया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हुए

कहा कि आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, जब हम लगातार आठवीं बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। **उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश दुनिया में जाएगा।**

उन्होंने कहा कि गीता केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। गीता सार्वभौमिक व सार्वकालिक और आज भी गीता की सार्थकता उतनी ही है, जितनी उस समय थी। विश्व को सुखी बनाने के लिए, शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए गीता का संदेश आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में जब आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा, इसके लिए गीता से कोई बड़ा साधन नहीं है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया के दर्जनभर देश ऐसे हैं जो हमें अपने यहां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का

आयोजन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा के रीजनल सेंटर बनाने की बात कही है, जिसके लिए हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया है। विश्व की भाषाओं का एक केंद्र यहां खुलेगा और विश्वविद्यालय में गीता का भी केंद्र है, जिसके माध्यम से हम दुनिया के बहुत देशों को एक प्लैटफॉर्म पर जोड़कर गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचा सकते हैं।